जवेरिया अब्दुल मजीद पाटनी

बनाम

आतिफ इकबाल मन्सूरी और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2069/2014)

18 सितंबर, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और एस.ए. बोबडे, जेजे.]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:

धाराएँ 2(ए) और (एफ) - अभिव्यक्तियाँ 'व्यथित व्यक्ति', और 'घरेलू नातेदारी' - समझाया गया।

धारा 12 सपठित धारा 18 से 23 - 'व्यथित व्यक्ति' (पत्नी) को आर्थिक राहत - एक बार घरेलू हिंसा कारित करने के बाद, तलाक की बाद की डिक्री प्रत्यर्थी को किए गए अपराध से मुक्त नहीं करेगी या उस लाभ से वंचित नहीं करेगी जिसके लिए व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हकदार है - भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि एसएलपी के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी ने मुफ्ती से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एकपक्षीय खुला (तलाक) प्राप्त कर लिया है, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत याचिका कायम रखने योग्य है।

मुस्लिम कानून;

'खुला' - समझाया गया।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1.1. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(ए) यह स्पष्ट करती है कि घरेलू रिश्ते में रहने वाली महिला के अलावा, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू रिश्ते में रहने वाली किसी

भी महिला पर, यदि आरोप लगाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का मामला "व्यथित व्यक्ति" के अर्थ में आता है। धारा 2(एफ) घरेलू नातेदारी को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार एक व्यथित व्यक्ति (पत्नी), जो किसी भी समय अपने पति के साथ साझा घर में रहती है, को भी "घरेलू नातेदारी" के अर्थ में कवर किया गया है। अधिनियम की धारा 2(एस) के मद्देनजर, यदि पीड़ित व्यक्ति' (पत्नी) किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थी (पति) के साथ एक घर में घरेलू रिश्ते में रहता है, तो व्यथित व्यक्ति "साझा घर" का दावा कर सकता है . [पैरा 20] [494-ए, बी, ई; 495-डी]

1.2. अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत निर्धारित धनिय राहत भरण पोषण से अलग है, जो सीआरपीसी की धारा 125 या कोई अन्य कानून के तहत भरण पोषण के आदेश के अतिरिक्त हो सकती है। इस तरह की धनिय राहत घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति के बच्चे द्वारा किए गए खर्चों और उठाए गए नुकसान को पूरा करने के लिए दी जा सकती है, जो इस सवाल पर निर्भर नहीं है कि क्या व्यथित व्यक्ति, दाखिल करने की तारीख पर धारा 12 के तहत आवेदन प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है। [पैरा 24] [501-बी-सी]

1.3. धारा 22 और 23 के मद्देनजर, यह मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है कि वह अंतरिम एकपक्षीय राहत दे सकता है जैसा कि वह उचित और उपयुक्त समझता है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि आवेदन प्रथम दृष्टया खुलासा करता है कि प्रत्यर्थी अपराध कर रहा है, या घरेलू हिंसा का कृत्य किया है या ऐसी संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर सकता है। धारा 18,19, 20, 21 और 22 के तहत उपलब्ध राहत किसी भी कानूनी कार्यवाही में मांगी जा सकती है, यहां तक कि आपराधिक न्यायालय के अलावा, सिविल न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय के समक्ष भी, व्यथित व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, चाहे ऐसी घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद

में शुरू की गई हो। यहां तक कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष भी जहां धारा 498ए के तहत मामला लंबित है, यदि आरोप सही पाया गया तो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत राहत और उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत मांगने के लिए अपीलार्थी हमेशा खुला है। [पैरा 25, 26, 27] [502-ए-डी; 503-ए-बी]

वी. डी. भनोट बनाम सविता भनोट 2012 (1) एससीआर 867= (2012) 3 एससीसी 183- पर निर्भरता।

इंदरजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2011 (10) एससीआर 557 = (2011) 12 एससीसी 588 - अप्रयोज्य निर्धारित।

1.4. 'खुला' तलाक का एक तरीका है जो पत्नी की ओर से होता है, पति केवल इस संबंध में उचित बातचीत के अधीन इनकार नहीं कर सकता है कि पत्नी ने बदले में उसे क्या देने की पेशकश की है। मुफ़्ती अपने स्कूल की शरीयत के आधार पर अपना फतवा या सलाहकारी निर्णय देता है। हालाँकि, यदि मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच गया है और निजी तौर पर इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है तो काजी (जज) को शरीयत के आधार पर क़ज़ा (फैसला) देना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, पति, प्रथम प्रत्यर्थी ने मुफ्ती द्वारा दिए गए 'खुला' को स्वीकार नहीं किया है जो शरीयत के आधार पर फतवा या सलाहकार निर्णय के रूप में है। हालाँकि, वह शरीयत के आधार पर क़ज़ा (फैसला) देने के लिए क़ाज़ी (जज) के सामने नहीं आया है। इसके बजाय, उन्होंने याचिका दायर करके 'खुला' के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए भी प्रार्थना की है। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी के लंबित रहने के दौरान 9.5.2008 को मुफ्ती से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एकपक्षीय

खुला (तलाक) प्राप्त कर लिया है, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत याचिका संधारण योग्य है। [पैरा 14-15 और 30] [491-बी-जी-ई; 504-एफ-जी]

मसरूर अहमद बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2007) आईएलआर 2 दिल्ली 1329; शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2002 (3) पूरक एससीआर 19 = (2002) 7 एससीसी 518 - संदर्भित किया गया।

1.5. एक बार घरेलू हिंसा का कृत्य करने के बाद, तलाक की बाद की डिक्री प्रत्यर्थी को किए गए अपराध से मुक्त नहीं करेगी या उस लाभ से इनकार नहीं करेगी जिसका व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत हकदार है, जिसमें धारा 20 के तहत धनिय राहत, धारा 21 के तहत बाल अभिरक्षा, धारा 22 के तहत मुआवजा और धारा 23 के तहत अंतरिम या एकपक्षीय आदेश भी शामिल है। [पैरा 31] [504-एच; 505-ए-बी]

हकदार है, उसमें शामिल हैं -

मामला कानून संदर्भः

2011 (10) एससीआर 557	अप्रयोज्य निर्धारित	पैरा 9
(2007) आईएलआर 2 दिल्ली 1329	संदर्भित किया	पैरा 13
2002 (3) पूरक एससीआर 19	संदर्भित किया	पैरा 16
2012 (1) एससीआर 867	भरोसा किया	पैरा 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2069/2014

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4250/2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.01.2013 से उत्पन्न।

समीर ए. वैद्य, शिल्पा सिंह, पंकज शर्मा, अपीलार्थी की ओर से।

पी. जनार्दनन, प्रदीप के.बी., अनिल कौशिक, गोपाल सिंह चौहान, के. सी. दुआ, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति. सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, के द्वारा दिया गया-

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 4250/2012 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 23 जनवरी, 2013 के निर्णय के खिलाफ दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेवरी, मुंबई द्वारा पारित 3 नवंबर, 2012 के आदेश को बरकरार रखा। जिसमे सत्र न्यायाधीश ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (इसके बाद "घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005" के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

3. अपीलार्थी का मामला यह है कि उसने 13 मई, 2005 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार प्रथम प्रत्यर्थी से विवाह किया था। प्रथम प्रत्यर्थी को उसे परेशान करने की आदत थी। उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और क्रूरता की गई। उदाहरण के लिए, प्रथम प्रत्यर्थी ने 5 जनवरी, 2006 को क्रूरता कारित की, उसे परेशान किया और उसकी पीठ और पेट को दीवार से टकराया। जिसके कारण उन्हें पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द हुआ। पहली प्रत्यर्थी ने 19 फरवरी, 2006 को उसे वैवाहिक घर में प्रवेश करने से मना कर दिया और उसे अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए कहा। उन्होंने 10 अगस्त, 2006 को ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पहली प्रत्यर्थी नवजात शिशु को देखने कभी नहीं आई। बाद में, पहले प्रत्यर्थी ने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की।

4. अपीलार्थी ने 6 सितंबर, 2007 को प्रथम प्रत्यर्थी, उसकी मां और उसकी बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 406 के तहत अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन

में एफआईआर संख्या 224/2007 दर्ज कराई। उसी के खिलाफ, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 1961/2007 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया और इसे प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई जिस पर इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया। इसके बाद, इस न्यायालय ने जुलाई, 2008 के आदेश द्वारा मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए रिट याचिका संख्या 1961/2007 को उच्च न्यायालय में भेज दिया। 4 दिसंबर, 2008 को, रिट याचिका संख्या 1961/2007 को उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रथम प्रत्यर्थी की मां और बहन के खिलाफ एफआईआर को इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया कि धारा 498 ए के तहत प्रथम दृष्टया मामला प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ बनता है।

5. अपीलार्थी के अनुसार, उसने 9 मई, 2008 को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुफ्ती से एकपक्षीय 'खुला' प्राप्त किया। प्रथम प्रत्यर्थी ने मुफ्ती द्वारा सुनाए गए 'खुला' को एम.जे. याचिका संख्या बी-175/2008 के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय, सैंड्रा के समक्ष चुनौती दी। उन्होंने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए भी याचिका दायर की।

6. 29 सितंबर, 2009 को, अपीलार्थी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18 से 23 के तहत राहत के लिए एसीएमएम की 46 वीं न्यायालय, मझगांव, मुंबई के समक्ष पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि वह खुद के साथ-साथ नाबालिग बच्चे को भी भरण-पोषण नहीं दे रहा है। प्रथम प्रत्यर्थी ने उक्त आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी पर प्रथम प्रत्यर्थी

द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गयी थी। लेकिन मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो गया, न्यायालय खाली हो गई और कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके बाद, अपीलार्थी ने अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया और मजिस्ट्रेट ने 4 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को 25,000/- रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश देते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया। भरण पोषण का भुगतान किए बिना, प्रथम प्रत्यर्थी ने मजिस्ट्रेट के 4 फरवरी, 2012 के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। सत्र न्यायालय, सेवरी, मुंबई ने 3 अगस्त, 2012 के आदेश द्वारा अपील दायर करने में हुई विलम्ब को क्षमा कर दिया और प्रथम प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई से पहले भरण-पोषण की पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया। चूँकि प्रथम प्रत्यर्थी ने राशि जमा नहीं की, अपीलार्थी ने डिस्ट्रेस वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया। तदनुसार, 1 सितंबर, 2012 को एक नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने बार-बार कहा कि पहले प्रत्यर्थी ने सत्र न्यायालय के समक्ष पैसा जमा कर दिया था और 4 फरवरी, 2012 के आदेश को वापस लेने और इस आधार पर आवेदन को खारिज करने के लिए 3 सितंबर, 2012 को दो आवेदन दायर किए थे। अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के बीच घरेलू नातेदारी मौजूद नहीं थे।

7. सत्र न्यायाधीश, सेवेरी, मुंबई ने दिनांक 3 नवंबर, 2012 के आदेश द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा:

> "14. सबसे पहले मैं उस कानूनी बिंदु को लूंगा जो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उठाया है कि क्या पक्षकारों के बीच 09/05/2008 को हुए तलाक पर दोनों पक्षों के बीच घरेलू नातेदारी थे। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि तलाक प्रथा के अनुसार हुआ है, फिर भी सिविल न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं

की गई है। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि अनावेदक ने स्वयं इस तिथि के बाद वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए कार्यवाही दायर की और रीति-रिवाज द्वारा प्राप्त तलाक को रद्द करने के लिए कार्यवाही भी दायर की। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों पक्षों के बीच तलाक हो गया है। लेकिन इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें आवेदक की दलीलें देखनी होंगी. वह स्वयं एक मामला लेकर आई थी कि 09/05/2008 को मुफ्ती द्वारा विवाह भंग कर दिया गया था। उसने स्वयं आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज दाखिल किये जिसमें अनावेदक के साथ आवेदिका के निकाह के संबंध में की गई घोषणा को अमान्य घोषित कर दिया गया है। और इसलिए, आवेदक अब अपीलार्थी की पत्नी नहीं है, इद्दत की अवधि के बाद वह अपीलार्थी की पत्नी थी, इद्दत की अवधि के बाद वह किसी भी बंधन से मुक्त थी। वह स्वयं मामला लेकर आई थी कि 09/05/2008 के बाद वह अनावेदक की पत्नी नहीं रही। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह स्वयं इस प्रथागत तलाक के लिए आगे आई थी और गैर-आवेदक के अनुसार इसे एकतरफा प्राप्त किया गया था। इस पृष्ठभूमि में आवेदक यह कहकर ज्यादा गरम नहीं हो सकता कि यद्यपि उसने ऐसा तलाक लिया था, फिर भी सिविल न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है और साथ ही अनावेदक ने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना और उस तलाक को रद्द करने के लिए कार्यवाही दायर की है और इसलिए, उसे उसकी पत्नी माना जा सकता है।“

15. इसलिए, अब एक कानूनी प्रश्न उठता है कि क्या 09/05/2008 को हुए तलाक के मद्देनजर, इस याचिका को दायर करने

की तारीख 29/09/2009 को पक्षों के मध्य घरेलू नातेदारी मौजूद हैं? और यदि कोई घरेलू नातेदारी नहीं है तो क्या आवेदन विचारणीय है?

20. इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय और अन्य माननीय उच्च न्यायालय का यह निरंतर दृष्टिकोण है कि तलाक के बाद पक्षों के बीच घरेलू नातेदारी नहीं रह गए हैं। और इसलिए, तलाक की तारीख के बाद अधिनियम के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है। मौजूदा मामले में भी तथ्य कुछ ऐसे ही हैं और इसलिए, निर्धारित कानून लागू है। वर्तमान मामले में भी तथ्य समान हैं और इसलिए, निर्धारित कानून लागू होता है।

21..... तो, मैं यह निष्कर्ष पर पहुँचता हूं कि 09/05/2008 को पक्षों के मध्य तलाक के मद्देनजर पक्षों के बीच घरेलू नातेदारी नहीं रहे और इसलिए, अधिनियम के तहत 29/06/2009 को दायर किया गया यह आवेदन विचारणीय नहीं है और इसलिए, कोई अंतरिम राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह कहा जा सकता है कि आवेदक के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।

23..... अगर मैं यह मानता भी कि आवेदन विचारणीय है, तो ऐसी परिस्थितियों में यह मामले को नए सिरे से सुनवाई और ऐसे कारणों को दर्ज करने के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेज देता। लेकिन जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि प्रथम दृष्टया आवेदन स्वयं संधार्य योग्य नहीं है, इसलिए आवेदक के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है और इसलिए, मैंने कहा कि विवादित आदेश तुरंत रद्द किया जा सकता है।"

उपरोक्त निर्णय द्वारा सत्र न्यायाधीश ने अपील स्वीकार की और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 46 वीं अदालत, मझगांव, मुंबई द्वारा पारित 4 फरवरी, 2012 के अंतरिम आदेश को अपास्त कर दिया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश की पुष्टि की।

8. इस न्यायालय के समक्ष पक्षों ने वैसी ही दलीलें दी हैं जैसी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ली गई थीं। अपीलार्थी के अनुसार कार्रवाई का कारण यानी घरेलू हिंसा तलाक से बहुत पहले हुई थी, इसलिए, एफआईआर दर्ज की गई और इसलिए अपीलार्थी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत राहत की हकदार है। संरक्षण अधिकारी ने पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है कि अपीलार्थी पर घरेलू हिंसा प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा की गई थी।

9. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के अनुसार विवाह विच्छेद के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती। उनके समर्थन में इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2011) 12 एससीसी डी 588 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया।

10. हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

(i) क्या अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी का तलाक 9 मई, 2008 को हुआ है; और

(ii) क्या एक तलाकशुदा महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18 से 23 के तहत अपने पूर्व पति के खिलाफ राहत की मांग कर सकती है।

11. इस मुद्दे के निर्धारण के लिए, अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के बीच संबंध पर ध्यान देना आवश्यक है। यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ने मुस्लिम रीति और रिवाज के अनुसार पहले प्रत्यर्थी से 13 मई 2005 को विवाह किया। तब से उनका रिश्ता घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित 'घरेलू

रिश्ता' था। वे दोनों घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित 'साझा घर' में एक साथ रहते थे, जब वे विवाह से संबंधित हैं/थे।

12. अपीलार्थी ने दलील दी थी कि उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुफ्ती से एकपक्षीय 'खुला' प्राप्त किया है। लेकिन पहले प्रत्यर्थी ने इसे स्वीकार नहीं किया है और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त 'खुला' को एम.जे.याचिका संख्या बी-175/2008 के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय, सैंड्रा के समक्ष चुनौती दी है। प्रत्यर्थी ने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए भी याचिका दायर की है।

13. मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह विच्छेद की अवधारणा को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मसरूर अहमद बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2007) आईएलआर 2 दिल्ली 1329 में देखा और चर्चा की। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीकों पर ध्यान दिया और अभिनिर्धारित किया:

> "15. सवाल यह उठता है कि शरीयत और उसके विभिन्न विद्यालयों को देखते हुए, कोई व्यक्ति उस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ता है जो विवाद में है? समाधान यह है कि जिन मामलों को निजी तौर पर सुलझाया जा सकता है, उनमें व्यक्ति को केवल अपने स्कूल के मुफ्ती (न्यायशास्त्री) से परामर्श करने की आवश्यकता है। मुफ़्ती अपना फ़तवा या सलाहकारी निर्णय अपने स्कूल की शरीयत के आधार पर देता है। हालाँकि, यदि कोई मामला मुकदमेबाजी के बिंदु तक पहुंच गया है और निजी तौर पर तय नहीं किया जा सकता है तो काजी (न्यायाधीश) को शरीयत के आधार पर क़ज़ा (फैसला) देने की आवश्यकता होती है (क़ाज़ी (या क़दी) राजनीतिक प्राधिकारी या राज्य द्वारा नियुक्त न्यायाधीश होता है) वह तलाक, विरासत, संपत्ति,

संविदा संबंधी विवाद आदि सहित कई कानूनी मामलों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय पारित कर सकता है। सेचेट, पृष्ठ 188। क़ज़ा या कड़ा एक निर्णय है, जिसे उस मदहब के अनुसार दिया जाना चाहिए जिससे क़दी संबंधित है, सेचेट, पी.196। काज़ियों और क़ज़ाओं के बारे में अधिक जानकारी पृष्ठ 188-198 पर पाई जा सकती है।) फतवे और क़ज़ा के बीच के अंतर को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। फतवा केवल सलाह है जबकि क़ज़ा बाध्यकारी है। बेशक, दोनों को शरीयत पर आधारित होना चाहिए, न कि शरीयत की निजी व्याख्या पर (अब्दुर रहीम, पृष्ठ 172 (क़ाज़ी के सम्बन्ध में)।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 और विवाह विच्छेद के विभिन्न रूपों को इसके द्वारा मान्यता दी गई है।

16. भारत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के अधिनियमन द्वारा मुस्लिम कानून के हिस्से के रूप में प्रथागत कानून के आवेदन के संबंध में भ्रम को शांत किया गया था। 1937 अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:-

2. मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ का अनुप्रयोग.- इसके विपरीत किसी भी रीति-रिवाज या उपयोग के बावजूद, बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में सभी प्रश्नों (कृषि भूमि से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर), महिलाओं की विशेष संपत्ति, जिसमें विरासत में मिली या अनुबंध या उपहार के तहत प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत कानून, विवाह, विघटन के किसी भी अन्य प्रावधान शामिल हैं। तलाक, इला, ज़िहार, लियान, खुला और मुबारत सहित विवाह, भरण-पोषण, मेहर, संरक्षकता, उपहार, ट्रस्ट और न्यास संपत्तियों और वक्फ (दान और धर्मार्थ संस्थानों और धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती के अलावा) मामलों में निर्णय का नियम जहां पक्षकार मुस्लिम हैं, वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होगा।

मुख्य शब्द इसके विपरीत किसी भी रीति-रिवाज या उपयोग के बावजूद हैं और उन मामलों में निर्णय का नियम जहां पक्ष मुस्लिम हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) होगा। इस प्रावधान के लिए उस न्यायालय की आवश्यकता होती है जिसके समक्ष, अन्य बातों के अलावा, विवाह विच्छेद से संबंधित कोई भी प्रश्न चल रहा हो और जहां पक्षकार मुस्लिम हों, उन्हें किसी भी विपरीत परंपरा या उपयोग के बावजूद मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) लागू करना होगा। यह न्यायालय पर एक निषेधाज्ञा है (देखें: सी. मोहम्मद यूनुस बनाम सैयद उन्निसा: 1962 1 एससीआर 67)। अभिव्यक्ति का भी बहुत महत्व है - 'विवाह विच्छेद, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला और मुबारत शामिल है। यह इस तथ्य को वैधानिक मान्यता देता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, विवाह का विघटन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें से केवल एक तलाक है। हालाँकि इस्लाम तलाक को घृणित और घृणित मानता है, फिर भी व्यावहारिकता के आधार पर इसकी अनुमति है, जिसके मूल में एक अपरिवर्तनीय रूप से टूटे हुए विवाह की अवधारणा है। सभी संभावनाओं का ध्यान रखने के प्रयास में, विभिन्न स्कूलों के तहत अलग-अलग आयाम और चौड़ाई के साथ, विवाह विच्छेद के तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई गई है। उदाहरण के लिए, खुला, विघटन का एक तरीका है जब पत्नी वैवाहिक बंधन को जारी नहीं रखना चाहती है। वह अपने पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखती है। बदले में कुछ देने की उसकी पेशकश के साथ यह हो भी सकता है और नहीं भी। आम तौर पर, पत्नी महर (दहेज) पर अपना दावा छोड़ने की पेशकश करती है। खुला एक तलाक है जो पत्नी से प्राप्त होता है, जिसे पति केवल पत्नी द्वारा बदले में उसे क्या देने की पेशकश के संबंध में उचित बातचीत के अधीन इनकार नहीं कर सकता है। मुबारत वह जगह है जहां पति-पत्नी दोनों आपसी सहमति से अपने वैवाहिक बंधन को खत्म करने का फैसला करते हैं। चूंकि यह आपसी सहमति से तलाक है, इसलिए पत्नी को पति को कुछ भी छोड़ने या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खुला और मुबारकत दोनों के

तहत तलाक के लिए कोई कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह तब होता है जब पत्नी (खुला के मामले में) या पत्नी और पति एक साथ (मुबारत के मामले में) बिना गलती/दोष के आधार पर अलग होने का फैसला करते हैं। भारत में विवाह विच्छेद के एक तरीके के रूप में खुला (और कुछ हद तक मुबारत) का सहारा लेना काफी आम है।"

14. उपरोक्त चर्चा से, हमने पाया कि 'खुला' विवाह विच्छेद का एक तरीका है जब पत्नी वैवाहिक बंधन को जारी नहीं रखना चाहती है। मामले को निजी तौर पर निपटाने के लिए, पत्नी को केवल अपने स्कूल के मुफ्ती (न्यायशास्त्री परामर्शदाता) से परामर्श करने की आवश्यकता है। मुफ़्ती अपने स्कूल की शरीयत के आधार पर अपना फतवा या सलाहकारी निर्णय देता है। इसके अलावा, यदि पत्नी वैवाहिक बंधन को जारी नहीं रखना चाहती है और विवाह विच्छेद के लिए 'खुला' का तरीका अपनाती है, उसे विवाह विच्छेद के लिए अपने पति को प्रस्ताव देना आवश्यक है। बदले में कुछ देने की उसकी पेशकश के साथ यह हो भी सकता है और नहीं भी। पत्नी महर (दहेज) पर अपना दावा छोड़ने की पेशकश कर सकती है। 'खुला' तलाक का एक तरीका है जो पत्नी की ओर से होता है, पति केवल इस संबंध में उचित वार्तालाप के अधीन इनकार नहीं कर सकता है कि पत्नी ने बदले में उसे क्या देने की पेशकश की है। मुफ़्ती अपने स्कूल की शरीयत के आधार पर अपना फतवा या सलाहकारी निर्णय देता है। हालाँकि, यदि मामला मुकदमेबाजी तक पहुँच गया है और निजी तौर पर तय नहीं किया जा सकता है तो काजी (न्यायाधीश) को शरीयत के आधार पर क़ज़ा (फैसला) देना आवश्यक है।

15. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने कहा कि उसने 9 मई, 2008 को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुफ्ती से एक पक्षीय 'खुला' प्राप्त किया है। अपीलार्थी या प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा न तो इसकी दलील दी गई है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि

क्या ऐसे 'खुला' के लिए अपीलार्थी ने पति-प्रथम प्रत्यर्थी को विवाह विच्छेद के लिए प्रस्ताव दिया था और बदले में कुछ देने की पेशकश भी की थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने मेहर (दहेज) पर अपना दावा छोड़ दिया है या नहीं। पति, प्रथम प्रत्यर्थी ने मुफ्ती (न्यायपालिका परामर्श) द्वारा दिए गए 'खुला' को स्वीकार नहीं किया है जो शरीयत के आधार पर फतवा या सलाहकार निर्णय के रूप में है। हालाँकि, वह शरीयत के आधार पर क़ज़ा (फैसला) देने के लिए क़ाज़ी (जज) के सामने नहीं आया है। इसके बजाय, वह एम.जे. याचिका संख्या बी-175/2008 दायर करके 'खुला' के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय, सैंड्रा के समक्ष चले गए हैं। उन्होंने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए भी प्रार्थना की है। इसलिए, बिना किसी निश्चितता के, यह कहा जा सकता है कि तलाक 9 मई, 2008 को लिया गया था।

16. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2002) 7 एस.सी.सी. 518 में, इस न्यायालय ने इस्लामिक कानून में 'तलाक' को वैध माना। इस न्यायालय ने पवित्र कुरान द्वारा निर्धारित 'तलाक' के सही कानून पर चर्चा करते हुए कहा कि तलाक एक उचित कारण के लिए होना चाहिए और दो मध्यस्थों द्वारा पति और पत्नी के बीच सुलह के प्रयासों से पहले होना चाहिए - एक पत्नी के परिवार से और दूसरा पति के परिवार से; यदि प्रयास विफल हो जाते हैं तो तलाक प्रभावी हो सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि तलाक को प्रभावी होने के लिए उसे घोषित किया जाना चाहिए।

17. उक्त मामले में, मुस्लिम महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा किया। पति-प्रत्यर्थी नंबर 2 ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में दायर अपने लिखित बयान में अपनी पत्नी, आवेदक पर धारा 125 सीआरपीसी के तहत तेज़, चतुर और शरारती होने का आरोप लगाया और कहा कि पत्नी की ऐसी सभी अनुचित गतिविधियों से तंग आकर उसने 11 जुलाई

1987 को उसे तलाक दे दिया। इस न्यायालय ने देखा कि कथित तलाक के विवरण की दलील नहीं दी गई थी और यहां तक कि मुकदमे के दौरान भी, पति ने स्वाम की परीक्षा में 11 जुलाई, 1987 को उसके द्वारा दिए गए तलाक के सबूत में कोई साक्ष्य नहीं दिया। आगे यह देखा गया कि तलाक के औचित्य में कोई कारण नहीं था और कोई दलील या सबूत नहीं था कि तलाक से पहले सुलह का कोई प्रयास किया गया था। इसके बाद, यह माना गया कि 11 जुलाई, 1987 को हुए तलाक का कोई सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने जिसे तलाक के रूप में बरकरार रखा है वह लिखित बयान में ली गई दलील है और 5 दिसंबर, 1990 को लिखित बयान की एक प्रति पत्नी को देकर बताई गई है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अतीत में कुछ समय पहले दिए गए तलाक के लिखित बयान में ली गई दलील को पत्नी को लिखित बयान की प्रति की डिलीवरी की तारीख पर तलाक के रूप में नहीं माना जा सकता है। पति को साक्ष्य पेश करना चाहिए था और 11 जुलाई, 1987 को तलाक की घोषणा को साबित करना चाहिए था। और यदि वह लिखित बयान में उठाई गई दलील को साबित करने में असफल रहा, तो दलील को असफल माना जाना चाहिए।

18. वर्तमान मामले में, जैसा कि देखा गया है कि अपीलार्थी या प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कोई निश्चित दलील नहीं दी गई है कि 'खुला' मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार प्रभावी हो जाता है। न तो अपीलार्थी और न ही प्रथम प्रत्यर्थी ने ऐसे तलाक के समर्थन में कोई साक्ष्य दिया। कोई विशेष दलील नहीं दी गई कि अपीलार्थी ने अपने पति-प्रथम प्रत्यर्थी को विवाह विच्छेद के लिए प्रस्ताव दिया हो। दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि 'खुला' का उच्चारण मुफ्ती ने एकपक्षीय रूप से किया था। उक्त कारण से, पहले प्रत्यर्थी ने पारिवारिक न्यायालय, सैंड्रा के समक्ष एम.जे.याचिका संख्या बी-175/2008 दायर करके इसे चुनौती दी। इस पृष्ठभूमि में, हम मानते हैं कि सत्र न्यायाधीश, सेवरी, मुंबई ने 3 नवंबर, 2012 के आदेश द्वारा गलत तरीके से टिप्पणी की और यह माना कि अपीलार्थी अब पहले प्रत्यर्थी की पत्नी नहीं है। उच्च न्यायालय भी यह ध्यान देने

में विफल रहा कि अपीलार्थी या प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। यह इस तथ्य की सराहना करने में भी विफल रहा कि 'खुला' मुफ्ती से प्राप्त किया गया था, काजी से नहीं और इसे प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारिवारिक न्यायालय, सैंड्रा, मुंबई के समक्ष चुनौती दी गई और सत्र न्यायाधीश के फैसले को गलत ठहराया। इसलिए, बिना किसी निश्चितता के, यह कहा जा सकता है कि दलील, साक्ष्य और निष्कर्ष के अभाव में तलाक 9 मई, 2008 को हुआ है।

19. भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी ने 9 मई, 2008 को 'खुला' (तलाक) ले लिया है। और पहला प्रत्यर्थी अब पति नहीं है, सवाल उठता है कि ऐसे मामले में क्या पूर्व पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20, 21, 22 के तहत निर्धारित एक या अन्य राहत और धारा 23 के तहत अंतरिम राहत का दावा कर सकती है? यदि घरेलू हिंसा तब हुई हो जब पत्नी अपने पति के साथ विवाह की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से साझा घर में रहती थी।

20. ऐसे मुद्दे के निर्धारण के लिए, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना वांछनीय है, जैसा कि यहां चर्चा की गई है:

(20.1) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(ए) "व्यथित व्यक्ति" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

> "2(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलु नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि उस महिला के अलावा जो घरेलू रिश्ते में है, कोई भी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू रिश्ते में रही है। यदि प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है तो यह "व्यथित व्यक्ति" के अर्थ में आता है।

(20.2) घरेलू नातेदारी की परिभाषा इस प्रकार हैः

“2(एफ) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्त्ता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा सम्बंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुदुम्ब के सदस्य हैं”

उपरोक्त प्रावधान से हम पाते हैं कि एक व्यक्ति व्यथित (यहाँ पत्नी), जो किसी भी समय एक साझा घर में पति (प्रथम उत्तरदाता) के साथ रही हो, "घरेलू नातेदारी" के अर्थ से भी कवर किया जाता है।

(20.3) धारा 2(एस) "साझी गृहस्थी" को परिभाषित करती है।

“2(एस) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तत: स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकारी, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है;”

इसलिए, यदि 'व्यथित व्यक्ति' (यहाँ पत्नी) किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थी (यहाँ पति) के साथ एक घर में घरेलू रिश्ते में रहती है, तो व्यथित व्यक्ति "साझी गृहस्थी" का दावा कर सकता है।

(20.4) धारा 3 में निर्दिष्ट "घरेलू हिंसा" की परिभाषा इस प्रकार है:

"3. घरेलू हिंसा की परिभाषा - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, -

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुँचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीडित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुँचाता है या संकटापन्न करता है; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुँचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

स्पष्टीकरण 1 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(i) "शारीरिक दुरुपयोग' से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीडा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है;

(ii) "लैंगिक दुरुपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है;

(iii) "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहास; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियाँ देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है;

(iv) आर्थिक दुरूपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, -

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हो या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक के संदाय, से वंचित करना;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इसके सदृश या अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रामण, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उनके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसका स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित करने वाली कोई अन्य संपत्ति; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुँच भी है, लगातार पहुँच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन।

स्पष्टीकरण 2 - यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसा"' का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।"

इसलिए 'शारीरिक दुरूपयोग' और लैंगिक दुरूपयोग' के अलावा, 'मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग' और' आर्थिक दुरुपयोग 'भी 'घरेलू हिंसा' का गठन करते हैं।

21. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का अध्याय IV "राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया" से संबंधित है। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"**12. मजिस्ट्रेट को आवेदन.-** (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है:

परन्तु जहाँ किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टयाँ जो विहित की जाएं या यथासम्भव उसके निकटतम रूप में अन्तर्विष्ट होगा।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।"

22. धारा 12 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, धारा 12 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक है।

23. राहत जो मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है, निम्नानुसार हैं।

(i) साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार- धारा 17

(ii) संरक्षण आदेश - धारा 18

(iii) निवास आदेश - धारा 19;

(iv) धनिय अनुतोष - धारा 20;

(v) अभिरक्षा आदेश - धारा 21;

(vi) प्रतिकार आदेश - धारा 22 और

(vii) अंतरिम और एकपक्षीय आदेश - धारा 23

24. तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18 से 23 के तहत राहत मांगी। इसमें धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश, धारा 20 के तहत धनिय अनुतोष, धारा 21 के तहत अभिरक्षा आदेश, धारा 22 के तहत प्रतिकार और धारा 23 के तहत अंतरिम राहत शामिल है। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

"**20. धनीय अनुतोष. -** (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी सन्तान को उपगत व्यय और कारित नुकसान की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी -

(क) उपार्जनों की हानि ;

(ख) चिकित्सीय खर्चे ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि; और

(घ) उसकी सन्तान, यदि कोई हों के साथ-साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण पोषण, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्थ है, संगत होगा।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियाँ, अपेक्षा करें, भरण-पोषण के एक समुचित एकमुश्त सदाय या मासिक सदाय का आदेश देने की शक्ति होगी।

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दी गई धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबन्धनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक को या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा।"

धारा 20 के तहत निर्धारित धनिय अनुतोष भरण-पोषण से भिन्न है, जो सीआरपीसी की धारा 125 या किसी अन्य कानून के तहत भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त हो सकती है। इस तरह की धनिय अनुतोष घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति के बच्चे द्वारा किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए दी जा सकती है, जो इस प्रश्न पर निर्भर नहीं है कि क्या धारा 12

के तहत आवेदन दाखिल करने की तिथि पर व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है।

25. धारा **22. प्रतिकर आदेश.-** अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षति के लिए, जिसके अन्तर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक संकट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा।

धारा 23. अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति.- (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो उचित और न्यायोचित हो, पारित कर सकेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्टया कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या किया है, या यह कि यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, यथास्थिति, धारा 22 के अधीन व्यथित व्यक्ति के शपथपत्र के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकगा।"

इसलिए, यह मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है कि वह अंतरिम एकपक्षीय राहत दे, जैसा कि वह उचित और उपयुक्त समझे। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि आवेदन प्रथम दृष्टया खुलासा करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कारित कर रहा है, या घरेलु हिंसा कारित किया है या इसकी संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कृत्य कर सकता है।

26. यह आवश्यक नहीं है कि धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत उपलब्ध राहत केवल घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही में मांगी जा सकती है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत उपलब्ध किसी भी राहत को आपराधिक न्यायालय के अलावा, सिविल न्यायालय और परिवार न्यायालय के समक्ष भी किसी भी कानूनी कार्यवाही में मांगा जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति पर प्रभाव चाहे ऐसी कार्यवाही घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले शुरू की गई हो या बाद में। यह घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 26 से स्पष्ट है जैसा कि यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

"**26. अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष.-** (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दाण्डिक न्यायालय के समक्ष व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात् आरम्भ की गई हो, ईप्सित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ कि व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा कर सकेगा, ईप्सित किया जा सकेगा।

(3) किसी मामले में, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।"

27. अपीलार्थी ने आई.पी.सी. की धारा 498ए के तहत किए गए अपराध के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज किया है। उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी की एफ.आई.आर. को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यहां तक कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष भी, जहां धारा-

498ए के तहत ऐसा मामला लंबित है, यदि आरोप वास्तविक पाया जाता है, तो अपीलार्थी के पास घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत राहत और उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत मांगने का विकल्प हमेशा खुला रहता है।

28. वी. डी. भनोट बनाम सविता भनोट (2012) 3 एससीसी 183 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले भी पक्षों के आचरण को धारा 18, 19 और 20 के तहत आदेश पारित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। वह पत्नी जो पहले एक परिवार में रहती थी, लेकिन अब अपने पति के साथ नहीं रह रही है, धारा 12 के तहत याचिका दायर कर सकती है यदि घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन हो। वी.डी. में भनोट (सुप्रा) ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> "12. हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक शिकायत पर गौर करते समय, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के लागू होने से पहले भी इसकी धारा 18, 19 और 20 के तहत एक आदेश पारित करते हुए पक्षों के आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है। हमारे विचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सही अभिनिर्धारित किया है कि भले ही एक पत्नी, जो अतीत में एक घर साझा करती थी, लेकिन अधिनियम लागू होने पर अब ऐसा नहीं कर रही थी, फिर भी वह पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2005 की सुरक्षा की हकदार होगी"

29. इंदरजीत सिंह ग्रेवाल (सुप्रा) में, अपीलार्थी-इंद्रजीत सिंह और उक्त मामले के प्रत्यर्थी नंबर 2 ने 23 सितंबर, 1998 को विवाह किया। विवाह के पक्षकार एक साथ ठीक से नहीं चल सके और उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया और, इसलिए, हिंदू

विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए मामला दायर किया। उक्त मामले में बयान दर्ज करने के बाद, कार्यवाही को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि वे इस मुद्दे पर विचार कर सकें। दोनों पक्ष दूसरे प्रस्ताव पर फिर से न्यायालय में उपस्थित हुए और उनके बयान के आधार पर, जिला न्यायाधीश, लुधियाना ने 20 मार्च, 2008 के फैसले और आदेश के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके विवाह को भंग कर दिया। विवाह विच्छेद के बाद, पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लुधियाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा प्राप्त तलाक की डिक्री एक दिखावटी लेनदेन थी। आगे आरोप लगाया गया कि तलाक लेने के बाद भी वे दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे. उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पूरी जांच करायी गयी और बताया कि विवाह विच्छेद के बाद दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे थे। इसलिए, इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि उक्त तलाक को चुनौती देने वाली घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धारा 12- 'मजिस्ट्रेट को आवेदन' न्याय के हित में और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वीकार्य नहीं है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं। उक्त मामले में निर्धारित कानून वर्तमान मामले के निर्धारण के उद्देश्य से लागू नहीं है।

30. वर्तमान मामले में, कथित घरेलू हिंसा जनवरी, 2006 और 6 सितंबर, 2007 के बीच हुई थी जब अपीलार्थी द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498 ए और 406 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 224/2007 दर्ज की गई थी। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ उक्त एफआईआर को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ धारा 498 ए के तहत मामला बनता है। भले ही यह स्वीकार कर

लिया जाए कि इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी ने 9 मई, 2008 को मुफ्ती से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एकपक्षीय खुला (तलाक) प्राप्त कर लिया है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका, 2005 कायम रखने योग्य है।

31. घरेलू हिंसा का कोई कृत्य एक बार किया गया, तलाक की बाद की डिक्री प्रत्यर्थी के किए गए अपराध के दायित्व से मुक्त नहीं होगी या उस लाभ से इनकार करना जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत हकदार है जिसमें धारा 20 के तहत धनिय अनुतोष, धारा 21 के तहत बाल अभिरक्षा, धारा 22 के तहत प्रतिकार और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत अंतरिम या एकपक्षीय आदेश शामिल है।

32. सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान देने में विफल रहे और यह तथ्य कि दोनों पक्षों के बीच कथित तलाक से बहुत पहले एफआईआर दर्ज की गई थी और यह मानने में गलती हुई कि धारा 12 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

33. उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका संख्या 4250/2012 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 23 जनवरी 2013 के आक्षेपित निर्णय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई द्वारा 3 नवंबर, 2012 को पारित आदेश को अपास्त करते हैं और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 46 वीं अदालत, मझगांव, मुंबई द्वारा पारित 4 फरवरी, 2012 के आदेश को बरकरार रखते हैं। प्रथम प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, यदि अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट अब मामले को आगे बढ़ाएंगे और रिपोर्ट का अध्ययन करने और पक्षों को सुनने के बाद अंततः घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका का निपटारा करेंगे।

34. उपरोक्त टिप्पणियों और दिशा-निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****